Notifications of the Ministry of Railways (Railway Board)

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): Sir, I beg to lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Railways (Railway Board):—

(i) S.O. No. 589(E), dated the 29th July, 1980.

(ii) S.O. No. 590(E), dated the 29th July, 1980.

(iii) S.O. No. 625(E), dated the 16th August, 1980.

(iv) S.O. No. 693(E), dated the 28th August, 1980.

[Placed in Library. *See* No. LT-1334/80 for (i) to (iv)].

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up Calling Attention.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

The delay in the implementation of the revised Palekar Tribunal Award on Journalist and Non-Journalist employees of Newspapers and News-agencies in the country

SHRI KALP NATH RAI (Uttar Pradesh): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Planning and Labour to the delay in the implementation of the revised Award of Palekar Tribunal on journalist and non-journalist employees of newspapers and news-agencies in the country.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): Sir, the Central Government had appointed a Wage Board for Non-Journalist Newspaper Employees in January, 1975 and another Wage Board for Working Journalists in February, 1976 under the provisions of the Working Journalists and Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 to fix the rates of wages in respet of working journalists and non-journalists newspaper employees. After submitting certain interim recommendations which were given effect to in April, 1977, these Boards found it difficult to continue to function due to differences among the members and withdrawal of the employers' nominees. The Boards were, therefore, replaced in February 1979 by one man Tribunal both headed by Shri D. G. Palekar, retired Judge of the Supreme Court by an amendment of the Act. The Tribunals submitted their recommendations to Government on the 13th August, 1980.

The then Minister of State in the Ministry of Labour met the representatives of the employees as well as the employers on the 10th and 11th September, 1980 to ascertain their views regarding the recommendations. Subsequently several representations were received from both the groups pointing out flaws in the recommendations seeking modifications therein. Later the Secretary of the Ministry of Labour met the representatives of the employers and the employees of the industry in a joint meeting on the 19th and 20th September, 1980 to see if they could reach a common understanding of the recommendations and if they could agree upon the modifications needed to be made therein. No agreement could, however, be reached at these meetings with regard to the modifications to the recommendations. It has now been left to the Government to take a decision in the matter.

The important comments received from the employers and the employees are as follows:—

Employees:

(i) The Tribunals have made substantial modifications from their tentative proposals regarding the scales of pay, rates of D.A., House rent allowance, night shift allowance, etc.

(ii) Certain recommendations regarding additional emoluments, additional allowances, dates of increment, etc. are not in confirmity with the law.

(iii) There are certain errors in the recommendations which are to the disadvantage of the employees.

(iv) Recommendations regarding fitment place the senior employees at a disadvantage as compared to the juniors.

(v) Certain recommendations involved reduction in the total emoluments.

Employers:

(i) The Tribunals have departed from the established law and practice regarding classification of newspaper establishments.

(ii) The Tribunals have not given due consideration to the capacity of the industry to pay the revised wages recommended by them, the financial burden that would be placed on the industry would be very heavy which the industry would not be able to bear.

(iii) Certain recommendations of the Tribunals relating to house rent allowance and night shift allowance were beyond their terms of reference and certain recommendations particularly those relating to part time correspondents are very unrealistic.

According to Section 12 of the Act the Central Government shall as soon as, may be, after receipt of the recommendtions from the Tribunals make an order in terms of the recommendations or subject to such modifications as it thinks fit. If the Central Government wishes to make modifications which effect important alterations in the character of the recommendations, the persons likely to be affected thereby are to be given notice and the representations which they may make in writing taken into account or the recommendations are to be referred back to the Tribunals before making the order.

The representations received from the employers as well as the employees have raised several legal issues and some of the demands made would seem to call for modifications which may or may not be construed as important alternations in the character of the recommendations. The legal and other aspects of the modifications sought by the two parties have, therefore, had to be considered carefully before taking a decision.

All these aspects are under consideration of Government. It is however expected that a decision would be taken very soon.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Before I ask Mr. Kalp Nath Rai to speak, I would like to inform the House that if this Calling-Attention Motion and the Special Mentions are not finished before 1-00 P.M., they will continue after the Half-an-Hour Discussion, Maybe at 5-30 P.M. or 6-00 P.M. today. So, kindly remember this. Yes, Mr. Kalp Nath Rai.

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदय, इस सारे देश में पालेकर अवार्ड को लेकर एक चर्चा बनी हुई है । आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जो हमारे लेबर मिनिस्टर है मै उनको बताना चाहता हूं कि अभी मुझे लखनऊ जाने का मौका मिला । लखनऊ में जनलिस्ट और नान जर्नलिस्ट के प्रतिनिधि मुझसे मिले । उन्होंने कहा कि पालेकर अवार्ड की सरकार को तुरन्त मोडिफिकेशन के साथ इम्पलीमेंट करना चाहिये । आप जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि महंगाई बहुत जोरों से बढ़ रही है । जनतंत्र मे तमाम न्यूज पेपर्स जो है वे प्रजातंत्र की नींव होते है । उसमें मालिक, एडीटर, जर्नलिस्ट, नान जर्नलिस्ट और कारेसपोंडेंट्स आदि मिलकर काम करते है । जब उनकी जिंदगी अच्छी होती है तभी वे देश के एक सतत प्रहरी बन सकते हैं । ऐसी स्थिति मे जो न्यूज पेपर्स के एम्प्लाइज है उनकी तनख्वाहो का लागू करने में, जबकि इस महंगाई को मद्देनजर

[श्री कल्पनाथ राय]

रखते हुए सेन्ट्रल एम्प्लाइज और स्टेट एम्पलाइज का कई बार पे रिविजन किया गया है, जबकि एवार्ड रिकमेंड हो चुका है तब सरकार इसमें क्यों देरी कर रही है ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हम इसको जल्दी एनाऊंस कर देंगे । सरकार की तरफ से जल्दी कहा गया है तो मै पूछना चाहता हूं कि जल्दी का क्या मतलब है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना यानी क्या उसकी डेट होगी, किस डेट तक आप उसको एनाऊंस कर देंगें ? तीसरी चीज मैं यह कहूंगा कि पालेकर एवार्ड में छोटे छोटे न्यूज पेपर भी हैं । उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है । अगर वह उसे रिकमेंड करेंगे तो उनके अखबार बिल्कुल खत्म हो जायेंगे या दिवालिया बन जायेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि इन छोटे-छोटे अखबारों की रक्षा के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? सरकार को जर्नलिस्टों ने जो रिप्रेजेन्टेशन किया है, मोडिफिकेशन के लिये तो एम्पलायर और एम्पलायज दोनों को बैठा कर सरकार क्या किसी एग्रीड फार्मूले पर पहुंची है ? चौथी बात हमें यह पूछनी है कि नान जर्नलस्ट जो अखबारों में काम करते हैं जो इसके एम्पलाइज है, इस महंगाई के युग में उनको संकट का सामना करना पड़ रहा है और उनको गुजर करना मुश्किल हो रहा है । विशेषकर अखबारो के जो इम्प्लाइज शहरों में काम करते हैं, बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है और चूंकि अखबारों के जो गरीब इम्प्लाइज हैं वे शहरों में ही रहते हैं, इसलिए उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई है । गांवों में महंगाई का संकट उतना नहीं है जितना शहरो मे है । जो इम्प्लाइज अखबारों में काम करते है, जर्नलिस्ट्स, नान-जर्नलिस्ट्स और कारस्पोन्डेन्ट्स आदि, उनको इस महंगाई के संकट का मुकाबला करना पड़ रहा है । मैं सरकार से और विशेषकर अपने लोकप्रिय, पोपुलर मंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी जी से चाहूंगा जिनके पास श्रम मंत्रालय का कार्य-भार है कि वे इस एवार्ड को मोडिफिकेशन के साथ जो उसमें कमियां हैं, जो डिस्टोरेशन्स है, उन्हें दूर करके इस एवार्ड को लागू करें । इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन का जो नजरिया है और हिन्दुस्तान के वेज स्ट्रक्चर में जो खामियां हैं, आज हमारे मुल्क के आजाद होने के बाद 32 सालो में भी हमारे देश के वेज स्ट्रक्चर में जो डिस्पेरिटीज हैं उनको दूर करने के लिए क्या प्लानिंग कमीशन कोई कदम उठाएगा ? हमारे मुल्क के अन्दर वैलेन्स सर्विसेज क्रिएट की जा सकें, क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाएगी ? श्रीमन, मै स्पष्ट रूप से यह निवेदन करना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि इस तारीख तक पालेकर एवार्ड की रिकमेन्डेशन्स को मोडिफिकेशन्स के साथ घोषित कर दिया जाएगा? उपसभापति महोदय, आप जानते हैं कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि इम्प्लायर्स की तरफ से लगातार यह दबाव डाला जा रहा है कि जर्नलिस्ट्स की तनख्वाह को इसकी रिकमेन्डेशन्स में न लाया जाय । आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान की जो पेपर इंडस्ट्री है, जो अखबारों के इम्प्लायर्स हैं वे टाटा, बिरला और डालमिया जैसे बड़े-बड़े लोग हैं । इसलिए मंत्री महोदय को कर्मचारियों के वेतन-मानों में इस प्रकार से संशोधन करने चाहिए जिससे वे सच्चे मायनों में देश की सेवा कर सकें । अखबार किसी मुल्क के प्रजातंत्र में आंख और कान होते हैं । ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इम्प्लाइज के हितों को मद्देनजर रखते हुए इम्प्लायर्स जो दबाव डाल रहे है उसमें न आकर पालेकर एवार्ड की रिकमेंन्डेशन्स को मोडिफिकेशन्स के साथ जर्नलिस्ट्स के पक्ष में लागू करने की सरकार कृपा करे ।

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : श्रीमन्, मै विद्वान सदस्य,

जो आजमगढ़ मे आते हैं, उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाया है(*Interruptions*)आप जानते हैं, आजमगढ़ शहरों में भी आजम शहर है। श्रीमन्, पालेकर एवार्ड के संबंध में यह सही तथ्य है कि पिछले महीनों में जब से यह एवार्ड आया है तब से बहुत चर्चा का विषय रहा है। जैसा कि मेरे विद्वान सहयोगी ने अपने वक्तव्य में कहा, इसमें दोनों पक्षों की ओर से बहुत से ऐसे वैधानिक प्रश्न उठाये गये हैं और ऐसे तथ्यों के संबंध में प्रश्न उठाये गये हैं कि जिनसे यह एवार्ड विवाद का विषय बन गया है और विशेष कर जो हमारे श्रमजीवी पत्रकार हैं उनके माध्यम से यह प्रश्न उठाया गया है। कि जो अन्तरिम प्रस्ताव पालेकर एवार्ड में कहे गये हैं उनको अंतिम प्रस्तावों में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। इसमें यह प्रश्न भी उठाया गया है कि धारा 12 जो वर्किंग जरनेलिस्ट्स एक्ट, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की है उसके अन्तर्गत क्या सिफारिशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, परिवर्धन और परिष्करण करने का अधिकार शासन को विधानतः है या नहीं ? ये मूल प्रश्न उठाये गये हैं। इसलिए ये वैधानिक प्रश्न उठाये जाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। लेकिन मैं विद्वान सदस्य को आपके जरिए से और इस परम सम्मानित सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि शासन इस पालेकर एवार्ड के सभी संवैधानिक और वैधानिक पहलुओं पर विचार करने के बाद संसद् के वर्तमान सत्र में ही इसके बारे में निर्णय ले लेगा और पार्लियामेंट में, संसद् में इसकी घोषणा कर देगा।

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, the newspaper industry is the only industry in this country where there has been no revision in the wage structure since 1967. For a number of years, the journalists and the press employees have been stagnant in their wage structures. And I would say that it is a known fact that the Government itself to its employees and the employees in the public sector undertakings and other employees has been giving from time to time higher DA and other benefits in order that the high rise in the cost of living could somehow be cushioned. The newspaper-owners have been getting away with a lot of, I would say, "bullying" all along. They boycotted the Wage Board that had been established in 1975. And because of their boycott, nothing could happen and after one year and a half this effort was given up. The Palekar Tribunal was then appointed. After a great deal of study, it announced its tentative proposals early this year. In August, the then Labour Minister announced the final recommendations of the Palekar Tribunal in Parliament. And at that time, he assured us that a final decision would be taken within a month on these recommendations and that the interests of the employees would be kept in mind. I want to point out here that much more than a month has since passed. the stalemate is continuing, and no decision has yet been taken by the Government inspite of repeated efforts and meetings with the Government which the employees have been having.

Sir, let me point out here that the tentative proposals were meaningful and were acceptable to most of the employees. But the final recommendations which the Tribunal has made after that go back from these interim or tentative proposals. For instance, even the Government gives Rs. 1.30 per point by way of DA. This was the interim recommendation. But in the final award it has been reduced to 83 paise per point. Now why the Tribunal should go back on its earlier recommendation, should go back from the Government-accepted formula is the question. Is it that the Tribunal succumbed to the pressure from the newspaper-owners or what was it that made it go back on its own interim recommendations? Secondly, they say that it is because of a clerical error, but it is being pointed out

[Shrimati Margaret Alva].

by the newspaper employees that 34 points have been missed out in the tabulations of the DA chart which the employees are asking to be restored so that they do not lose by it. Then, Sir, the city compensatory allowance, the house rent allowance and the night shift allowance have been abolished altogether with the result that many journalists are going to suffer because of this Award instead of benefiting by it. They have been pleading with the Government that the interim recommendations should be restored. You have assured that you would look into their grievences, you have promised to decide within one month. And that was in August. We are coming to December and no decision has yet been taken I would, therefore, like to ask the Government how much more time they wish to take.

MR DEPUTY CHAIRMAN: You have said that.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I will take just one more minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: About the time, he has said just now. He said, by the end of the session.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, I may point out here that there was already one-day strike by the employees and they are threatening an indefinite agitation. Before it comes to that, I would ask the Minister whether he has any definite proposals by which this deadlock can be sorted out. Sir, I would like to ask the Minister one more question. When it had been pointed out to the former Minister for Labour that the moment the announcement of this Award was made in Parliament, a number of correspondents had been terminated from service by newspapers around the country, he gave an assurance in the House at that time that he would see that no such terminations would take place and that their interests would be safeguarded. But I may point out here that after that assurance, many of them have been re-employed, but have been re-employed, under new contracts, making them what you call stringers'. There is no monthly salary. They are paid on the basis of published material whereas they were regular employees before their termination. This is not a fulfilment of the assurance which the Minister had categorically given, namely, that they would not suffer and that they will be re-employed. I would like an assurance from the hon Minister that this would also be looked into.

AN HON. MEMBER: Even the AIR has terminated the services of correspondents.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: Sir, I must commend the learned Member from Karnataka for making factually a statement which is substantially correct. I have already, on behalf of the Government, mentioned many of these facts myself. On page 2 of the statement the hon. Member will find that most of the facts mentioned by her are duly narrated in the remarks column. Well, I am not exactly sure about the assurance regarding the time-table given by my learned predecessor but I will again...

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): He gave it to me. He gave an assurance to me. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kulkarni, please sit down.

SHRI KALP NATH RAI: Sit down, Mr. Kulkarni.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: You are not in the Chair. Why are you asking me to sit down? It is the Chair who can ask Members to sit down.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: It will be duly announced within the session on the floor of Parliament, in

this august House. Then as far as the question regarding dismissal of certain employees is concerned, I would certainly like to be enlightened about the details and I would certainly like to carry out the assurance, if any such assurance has been given.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: The All India Radio has dismissed the correspondents because they do not want to pay emoluments comparable to Palekar award. This is the Government owned corporation, you must know.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): Because I am here and my friend is making allegations against my Ministry, I must categorically deny this allegation. We have not dismissed any correspondents because of the Palekar Tribunal's Award. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Bhattacharya.

SHRI G. C. BHATTACHARYA (Uttar Pradesh): Sir, ...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): Sir,....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mathur, don't worry, you will get your chance Mr. Mathur. Yes, Mr. Bhattacharya.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Sir, ... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, I will not allow. I will not allow.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Sir, ...

DR. RAFIQ ZAKARIA (Maharashtra): Sir, the hon. Member has said that the Minister is telling.* That is unparliamentary.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will look into that. Yes, Mr. Bhattacharya.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Sir, ...

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRI S. W. DHABE: Sir, ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, I will not allow that. I am not going to allow that way.

SHRI S. W. DHABE: Sir, ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dhabe will not go on record.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right, what is your point of order?

SHRI P. RAMAMURTI (Tamil Nadu): May I suggest to him a way out? If Mr. Kulkarni has got the facts and the Minister's statement is wrong, then I would suggest that he may give a Motion of Privilege against the Minister and be done with this matter. What is the use of shouting here?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all right.

SHRI VASANT SATHE: Sir, let us not confuse the matter and make it even worse. I had said it very clearly that as far as these part-time AIR correspondents were concerned, before also in this House, while making a statement last time, as soon as I came, that as the term of these correspondents was over, we had them throughout the country—it had nothing to do with the Palekar Award, it had not even come by that time—we had terminated the contract of the part-time correspondents, the A.I.R. correspondents. We are going to appoint fresh A.I.R. part-time correspondents all over the country. This has nothing to do with the Palekar Award. What is alleged by my friend is that in pursuance of the Palekar Award, as if to circumvent the Palekar Award, I have terminated or my Ministry has terminated some part-time correspondents. This I say is baseless. This has nothing to do with the Palekar Award. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dhabe, you cannot take the chance. I have called Mr. Bhattacharya now. No Mr. Dhabe, you please take your seat. He made some allegation and the Minister clarified it. No, Mr. Dhabe, you will not go on record.

(Shri S. W. Dhabe continued to speak)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If the Member does not follow the rules, I am sorry I will not allow him. A Member whose name is not there, cannot come in a different way circumventing the procedure and I shall discourage it.

(Shri S. W. Dhabe continued to speak)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your party was free to give your name. If you had better facts, your party should have given your name. I will not allow it. Unnecessarily you are wasting your time. Yes, Mr. Kulkarni, what is your point of order?

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Sir, Mr. Sathe has said that no termination has taken place. I will give him an example that after the publication of the Palekar Award, services of part-time correspondents of the All India Radio were terminated.

SHRI VASANT SATHE: I have said that Palekar Award has nothing to do with the AIR correspondents. Why are you trying to connect the two? You don't understand.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: AIR has to be an ideal employer.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now the matter is over.

SHRI VASANT SATHE: Mr. Kulkarni, I am capable of dealing with you on matters of All India Radio. Don't confuse Palekar Award. It has nothing to do with it.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: I am also competent to deal with you. The problem is of workers whom you have engaged on All India Radio.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now the matter is over. Mr. Bhattacharya.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Mr. Deputy Chairman, Sir, my colleague Mrs. Alva said that working journalists were not getting a revision since 1967. I just amend it. They are not getting since 1960. It is twenty years now. You know, invariably, every five years, the salaries of the employees which are guided or regulated by these statutory Awards are revised. That is the practice. But in this case, twenty years have gone by and nothing has been done.

Now, many things have been said. I would only ask one question. When Justice Palekar was appointed, or when these tribunals were announced, the employers and the employees were asked to supply materials and relevant facts. Nobody can say that there was anything wrong in the material supplied either from the employers' side or from the employees' side. Both the parties to the dispute did submit all the available and relevant material. And on the basis of this relevant and available material, Justice Palekar who was a judge of the Supreme Court—he is not an ordinary person or a person without any experience of law or the law courts and practices—decided that there should be an interim award. After all, this interim award did not come out of his own imagination. This interim award was based on the facts and the relevant data supplied by both the parties. Now, if on the basis of those facts this interim award came, then what are the new facts or the new materials which had been placed before the tribunal by which the Palekar Award was changed to the detriment of the working journalists and non-working journalists? This is my first question.

Secondly, I would like to know: Is it not a fact that after the interim award came pressures from the Jute Press and from the monopoly houses started building on the Government and one of the Ministers of the Government has said that this is not capable of being implemented. If this is so, the interim award was changed to the detriment of the working journalists under the pressure of both the Government and the monopoly houses. I would like to know: what is the legality? He has to say whether he has the power to amend the award. What is the legality? Under pressure from the monopoly houses and the newspaper employers, you amended the interim award which was based on facts supplied by the employers and the employees both. This is my second question. Thirdly, I would like to know from you, how you are justified, under what law, in reducing the emoluments. Can you cite a single example in industrial disputes, in the history of industrial jurisprudence, where, under any award, the existing emoluments have been reduced? This is exactly what is going to happen in this case and the existing emoluments and the facilities are going to be reduced. My fourth question is this. I have been able to establish that there is no legal basis. Rather, it is illegal The interim award could not have been changed. If this is the case, I would like to know whether he will implement the interim award of Mr. Palekar as soon as possible, or, as has been promised by him, during this Session.

श्री कल्पनाथ राय : कई प्रश्नों का जवाब तो पहले दिया जा चुका है।

श्री उपसभापति : ठीक है । जो कह दिया गया है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : मेरी एक भी बात का इसकी तरफ से जवाब नहीं आया है।

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: The learned and hon. Member from Allahabad has mentioned three points.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Four points.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: Four points. He has said that both the parties had submitted adequate material before the Tribunal.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: The materials were there and on the basis of these materials, the interim award came. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Minister has understood you. (*Interruptions*).

SHRI G. C. BHATTACHARYA: He has not even taken down my questions. He is dealing with this serious question in a non-serious way. He has not even taken down my questions.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not interrupt him. He is a very competent person. You should not worry.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: I would just point out to the hon. Member that on page 91, the Tribunal has itself made a remark that the newspaper proprietors were not fully responsive. It has said 'The Tribunal would have been happier if the newspaper proprietors had been more responsive in giving the necessary material and the information called for. Only about 17 newspaper establishments bringing about 219 newspapers came forward with the required material at the earlier stage when the Wage Board issued the questionnaire. But even some of them defaulted in updating the material when called upon to do so by the Tribunal.' (*Interruptions*).

What I am saying is that many of the newspaper proprietors did not co-operate fully with the Tribunal. The Tribunal has mentioned this. My learned friend is a renowned lawyer in Allahabad and he will kindly see the Act, the Working Journalists Act

[Shri Narayan Datt Tiwari]

and the statute which was passed especially while constituting the Palekar Tribunal. There is nothing like an interim award provided for in the statute.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: There was no bar.

(Interruptions).

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: I do not hold any brief for the Palekar Tribunal. If the hon. Member expects that I would hold any brief for the Palekar Tribunal, then I would like to say that I do not hold any brief for the Palekar Tribunal What I am just mentioning is that, under the law, there is no provision for an interim award. I am just mentioning the law and the facts.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Where is that? What is that law?

(Interruptions).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. Mr. Bhattacharya, please sit down.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I am entitled to know. I would like to know: what is the law which imposes a bar. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhattacharya, this is a very curious method. He is explaining. You should have the patience to hear him.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: You should help me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am helping you. Unless you hear him, how can I help you? On every sentence if you stand up and make a comment, nobody can reply. *(Interruptions)*. He is replying to that. Now please sit down. *(Interruptions)*

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: What happened was, under the procedure established by the Tribunal itself they formulated certain tentative proposals and those tentative proposals were modified by the Tribunal in its own wisdom, in its final report. For that the Government is not at all responsible. It is only the Tribunal that is responsible but it would be unfair to allege that the Tribunal was influenced by anybody. And I may assure the hon. Member that this Government has not been influenced by any person, in any manner, by any so-called jute press or any proprietor as mentioned, and when the decision of the Government of India is announced, he will himself in good conscience see that this is not so, and that our decision is equitable, legal, and fair.

Then the hon. Member said that the emoluments will be reduced. Of course, I cannot foreclose the decision that may be taken, but I must assure the hon. Member that whatever else be the decision, the existing moluments of the working or non-working journalists will be protected under section 16. We shall protect the existing emoluments. There is no question whatsoever of the Award being modified to reduce the emoluments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Buddha Priya Maurya—not there. Shri Shah—not there. Yes, Mr. Jagdish Prasad Mathur.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मंत्री जी ने आश्वासन तो काफी दिए हैं, पूरे कितने होंगे परमात्मा जाने। मुझसे पहले जो बोले हैं उन्होंने भी तथ्य रखे जिनका प्रतिवाद मंत्री जी ने किया है। मैं उनके सामने एक तथ्य रख देता हूं. . . *(Interruptions)*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उन्होंने कहा है, और ठीक कहा है जूट प्रेस की तरफ से शायद कोई दबाव नहीं आएगा लेकिन वह जानते होंगे कि तथ्य यह है कि जूट प्रेस और दूसरा प्रेस—जिसको मैं साम्यवादी कहूंगा कांग्रेस-आई कहूंगा—मिल कर दबाव डालते रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं

मंत्री जी से कि क्या यह सच नहीं है कि नेशनल हैराल्ड के मैनेजर श्री यशपाल कपूर 5 अगस्त 1980 के दिन बम्बई गए और उन्होंने ट्राइब्यूनल से डिसकस किया। दबाव डाला कि नहीं डाला? इट इज़ अ फैक्ट। यह इन्होंने ठीक कर दिया कि जट प्रेस ने प्रभाव नहीं डाला। ठीक है लेकिन इनके घर के आदमी ने नेशनल हैराल्ड के मैनेजर ने---इनकी तरफ से डाला और वह कांग्रेस-आई के बड़े नेता, अधिकारी है, यह सच है। तो अब आगे प्रभाव में नहीं आयेंगे ऐसी मेरी कम से कम विनती है। इन्होने कहा, इन्टेरिम रिपोर्ट आई; ठीक है, आई। आप उसको लागू नहीं कर सकते है, बिलकुल सच है कि नहीं कर सकते। लेकिन आपको मालम तो हो गया क्या हुआ है कुछ बातों से, ये तथ्य जो हमारे साठे साहब बात कर रहे है---सुन लें साठे साहब---इनका कहना है कि ट्राइब्यूनल के अवार्ड के बाद हमने नहीं हटाया। ठीक है। लेकिन जब उनको तथ्य मालूम हो गए कि ट्राइब्यूनल का अवार्ड क्या आने वाला है---उसको बीच में हटा दिया। समझ में नहीं आता आप क्या कह रहे हैं। आफिशियली जब आया तब आपने हटाया, उससे पहले आपको मालूम हुआ तब आपने हटाया। यानी, इम्प्लायर के नाते से जो चालाकी बिड़ला जी, टाटा जी आदि करते है, आपकी जानकारी के बिना इन अधिकारियों ने कर डाला। इसको आप ज़रा संभाल लें... (*Interruptions*) ...हो सकता है, इनकी सहमति हो। मैं तो बचाना चाहता हूं, शरीफ आदमी हैं ये---इम्प्लायर है।

नंबर दो: मंत्री जी ने कहा है कि कानूनी बाधाएं हैं, ठीक है। तो कानूनी बाधाओं को दूर करने के दो तरीके हैं। आप माइनर माडिफिकेशन बिना नोटिफिकेशन के कर सकते हैं। माइनर मोडिफिकेशन इस अवार्ड में क्या हो सकता है यह आप निर्णय कर ले। लेकिन अगर मेजर मौडिफिकेशन आपको करना हो तो आप कर सकते है, उसमें केवल आपको नोटिफिकेशन करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन करने के बाद दोनों पार्टियों को सुनना पड़ेगा और दोनों पार्टियों के ऊपर अपना दबाव डाल कर मनाना पड़ेगा। यह आप ने खुद कहा है कि कमीशन ने लिखा है---उसको मैं दोहराना नहीं चाहता---कि बहुत से मालिकों ने झूठे आंकड़े दिये हैं, गलत आंकड़े दिये है और उनको सुधारने की उन्होंने हिम्मत नहीं की। हर एम्प्लायर करता है। यह मैं नहीं कहता कि उन्होंने नहीं किया, जरूर करते हैं। लेकिन अब आप पर जिम्मेदारी है कि आप माइनर मोडीफिकेशन करना चाहते हैं या नही। मै उदाहरण देता हूं। कमीशन ने यह रिकमेंड किया है कि इन्क्रीमेंट जिस दिन से यह एवार्ड लागू होगा उस दिन से दिया जाये---शायद आप नोटिफिकेशन कर रहे है---लेकिन इससे हजारों रुपए का नुकसान एक कर्मचारी का हो जायेगा। यदि आप यह मोडीफिकेशन कर दें कि जो उसकी डेट आफ एपोइन्टमेंट है उस दिन से उसको बाकायदा इन्क्रीमेंट दिया जायेगा तो बहुत से कर्मचारियों का भला आप कर देंगे। यह मेजर मोडीफिकेशन नहीं है जिसके लिए कानूनी बन्धन हो। (*Time bell rings*) दो एक बातें तो कहने दीजिए।

श्री उपसभापति: एक-आध मिनट में खत्म करिये।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: दूसरे इसमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि यदि किसी का वेतन ऐसा है जो इस समय की रिकमेंडेशन के अनुसार ज्यादा बैठता है तो आगे उसके इन्क्रीमेंट बन्द करके उसकी पे के साथ बैठाया जायेगा। यह कौन सा तरीका है? तरीका यह है कि जिसको जितना वेतन मिलता है वह घट ही नहीं सकता। उसकी कोई गलती नहीं है।

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

इनडायरेक्टली आप उसकी आमदनी पांच साल तक बढ़ने से रोक रहे हैं। यह कहां का तरीका है? यह रांग है। यह माइनर मोडीफिकेशन है जो आप कर सकते हैं जिसके लिए कोई कानूनी बन्धन नही है।

मेरी बहिन अल्वा ने हाउस रेन्ट का जिक्र किया, डी० ए० का जिक्र किया। डी० ए० के लिए जो सरकारी कर्मचारियों पर कायदा लागू करते हैं वह यहां करने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं। इनके लिए कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स 329 आप ने बेस माना है। यह क्यों? इनके लिए 329 और सरकारी कर्मचारियों के लिए 360 आप ने माना है। अखबार वालों को आप .83 देंगे जब कि बाकी सरकारी कर्मचारियों को 1.83। यह भी माइनर मोडीफिकेशन के नाते कर सकते हैं और यह करना चाहिए।

ऐसे ही हाउस रेन्ट है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 परसेंट है शायद। आप ने जब समाचार बनाया तब 15 परसेंट दिया था। आप ने अब 15 परसेंट से काट कर 6 परसेंट कर दिया, जिनको ज्यादा मिलता था उनका काट दिया, जिनको नहीं मिलता है उनको 6 परसेट दिया। यह मेजर मोडीफिकेशन है जो आप नोटीफिकेशन से कर सकते हैं। यह 15 परसेंट हाउस रेंट मालिक देने को क्यों तैयार नहीं हैं?

तीसरी बात। मालिक चिल्ला रहे हैं कि हम मर जायेंगे। कोई मालिक कभी मरता नहीं। कमीशन ने खुद कहा है कि पिछली रिकमेंडेशन्स के बाद--मालिकों ने 76 में कहा था कि हम मर जायेंगे लेकिन मरे नहीं--400 परसेट मुनाफा हो गया। फिर भी आप अगर चाहते हैं तो तरीका निकाल सकते हैं। बड़े न्यूजपेपर्स को विज्ञापन गवर्नमेंट कामर्शियल रेट पर देती है। लेकिन गवर्नमेंट अपने विज्ञापन छोटे पेपरों को, मीडियम पेपरों को उस रेट पर नहीं देती। अगर कामर्शियल रेट उनको दे तो उनका फायदा हो जायेगा। न्यूजप्रिन्ट आपको बाहर से भी मंगाना पड़ता है। उस पर आप सेल्स टैक्स क्यों नहीं कम करते। मेरा निवेदन है कि आप विश्वास से काम लीजिए और माइनर मोडीफिकेशन जो आपके अधिकार में हैं उनको कर दीजिए और बाकी मेजर मोडीफिकेशन के लिए नोटीफिकेशन निकालिये, एम्प्लायर्स को कहिये कि जो उचित बातें हैं वह होनी चाहिएं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, विद्वान संसद्-सदस्य राजस्थान ने. . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं। मेरे नाम के राजस्थान के सदस्य लोक सभा में हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : विद्वान संसद सदस्य उत्तर प्रदेश ने--श्रीमन, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं, मेरी जानकारी उन्होंने बढ़ाई, मैं उनका आभारी हूं।

श्री प्रकाश मेहरोत्रा (उत्तर प्रदेश): यह उत्तर प्रदेश से राज्य सभा में आने के लिए हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं आभारी हूं, आप ने मेरी जानकारी बढ़ाई। उन की संसदीय प्रतिभा का मैं आदर करता हूं। लेकिन, श्रीमन्, यह प्रश्न राजनैतिक विरोधाभास की भावनाओं से परे मै मानता हूं और मैं यह आग्रह करूंगा विद्वान संसद-सदस्य से कि इस में कांग्रेस (आई) या राजनीति या पार्टियों का उल्लेख वह न करते तो अधिक संसदीय होता। श्रीमन्, यहां पर उन्होने श्री यशपाल कपूर का उल्लेख किया। मैं समझता हूं कि जो संसद सदस्य हैं वे उन का नाम सोच विचार कर लेते हैं ससद के सदस्य नहीं हैं या यहां पर प्रतिवाद करने के लिये

उपस्थित नहीं है और ऐसे लोगों पर आक्षेप लगाना विद्वान सदस्य जानते हैं कि उचित नहीं है । श्रीमन, इस संबध में मैं कहना चाहता हूं कि श्री यशपाल कपूर इस संबंध में हम से नहीं मिले और न उन्होंने इस प्रकार का कोई दबाव डाला ।

(Interruptions)

श्री उप-सभापति : आप सुन लीजिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जहां तक प्रश्न है माइनर माडिफिकेशन और मेजर माडिफिकेशन का, माननीय विद्वान सदस्य ने वही बात कही जो मैं कह रहा था । यही मैं देख रहा हूं कि धारा 12 (1) की परिधि के अन्तर्गत कौन से ऐसे संशोधन हैं कि जो इंपार्टेन्ट यानी महत्व शब्द की कानूनी परिधि से बाहर आते है या नहीं आते हैं । अगर वह धारा 12 (1) की परिधि में आते हैं तो कानूनी हैं, यही लिया जा रहा है । जितने विभिन्न सुझाव आये है उन में से कौन और कितने महत्व शब्द की कानूनी परिधि के अन्तर्गत आते हैं और कितने नहीं आते हैं और फिर अगर वह महत्वपूर्ण संशोधन हैं—इंपार्टेंट आल्टरेशन्स इन दि करेक्टर आफ रेकमेंडेशन्स हैं तो उस के लिये धारा 12 (2) का प्रयोग करना होगा । नोटिस देना होगा । अभी तक ट्रिबुनल बनाने के अलावा नोटिस देने का कोई प्रबन्ध नही था, लेकिन 11 नवम्बर को शासन ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है जिस में 30 दिन का नोटिस दिया जा सकता है और उन्हें लिखित रूप से 30 दिन का वक्त दिया जा सकता है और उस के बाद निर्णय लिया जा सकता है । इसके लिये, रास्ता खोल दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी निर्णय लेना हो तो लिया जा सके । तो माइनर माडिफिकेशन कौन हैं और मेजर कौन हैं उस के संबंध में माननीय सदस्य ने जो राय दी है उस पर हम विचार करेंगे और अगर वह माइनर मोडिफिकेशन निकलते हैं तो इस से अच्छी बात क्या हो सकती है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ramamurti.

SHRI KALP NATH RAI: Another learned man.

SHRI P. RAMAMURTI: Sir, many questions have been raised, but I would like to point out to the Minister that in the tripartite conference to which the hon. Minister made a reference and which was held in September last, both the parties—it is a surprising thing—the employees' representatives as well as the employers' representatives did not want the matter to be further postponed. If you want to make major modifications, you will have to give some notice or you have to send it back to the Tribunal. All these things are there. So, both the parties had stated that the Government should, within the Act, try to make such modifications as are necessary and announce them. Now I do not understand why the Government did not have its consultations with the Law Ministry even before calling the tripartite conference with regard to what exactly the legal position, the constitutional position is with regard to these things. Therefore, it was very easy. After all, this Award was given in the month of August. Both the parties are raising certain fundamental questions. Particularly when the employers were raising certain constitutional positions, the Government could have been ready with the answers to those things, the Government could have armed itself with them even before that. Therefore, where is the question of now going into that? For example, with regard to the question of D.A., the BPE formula is there. For all the public sector undertakings the BPE has given a guideline that it should be

[Shri P. Ramamurti]

1.30, and we are agitating against it. The entire public sector undertakings workers are agitated against it that this guideline will not do because this does not fully protect the rise in the cost of living. Here, it is giving something far less. So, this is not a major question at all. On this question at least, what is given to the public sector undertakings, what has been accepted by the Bureau of Public Enterprises (BPE) towards the public sector undertakings, that modification can be made very easily.

Now he has said that he will announce it before the end of this session. I am happy about it. Now I only want that this undertaking that has been given will not go the way the undertaking that was given by the previous Minister went. Of course, I do not blame him because within a few days he had to go. He went as the Chief Minister of Andhra Pradesh and you had to come. I understand the difficulty.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: He will go to Uttar Pradesh.

SHRI P. RAMAMURTI: I do not know. I hope you won't go away from here before announcing this. He says you will go to U.P. I do not know anything about it. All that I want is that this promise that this exercise will be done within the course of the next two weeks and before the session ends, this announcement will be made, be kept. That is all.

SHRI NARAYAN DUTT TIWARI: Of course, I respect the views of the honourable and learned Member. As I said, we will adhere to our decision and we will make the announcement within the Current Session.

श्री उपसभापति : श्री लाडली मोहन निगम । कृपया संक्षेप में पूछिये, समय बहुत कम है ।

श्री लाडली मोहन निगम : (मध्य प्रदेश) : कहिये तो नहीं पूछूं ।

श्री उपसभापति : ऐसा मैं नहीं चाहता । हाउस साढ़े पांच के बाद न चले, इसीलिए कह रहा हूं । यहां आप संक्षेप में पूछ सकते है ।

श्री लाडली मोहन निगम : उपसभापति महोदय, मुझे वे बातें नही कहनी है जो सदस्यों ने उठाई हैं लेकिन जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे है, उनके बारे में पूछूंगा । मसलन सरकार को रपट मिले करीब करीब तीन महीने हो चुके है । उसके बाद अलग अलग लोगों ने और खास कर उन संस्थानों ने जो इनसे संबंधित है, उन्होंने सरकार के पास अपने सुझाव भेजे । क्या अड़चनें थी, क्यों आप उस पर फैसला नहीं ले सके ? ये शक करने की गुंजाइश आप छोड़ देते है । मिसाल के लिए अगर आप जैसा कहते हैं और यह मानकर चलें कि हिन्दुस्तान के एकाधिकार वाले पोषक तत्वों के हिमायती आप नही हैं तो कुछ न कुछ तो किया जा सकता था । तत्काल आप मामूली चीजें तो आर्डिनेंस के जरिये कर सकते है और आप मानते हैं कि यह ऐसा तबका है जो 20 वर्षों से परेशान है, जिसकी सुविधा के मामले मे, वेतन के मामले में, महंगाई भत्ते के बारे में 20 साल से कुछ नहीं हुआ । तो कम से कम यह सुझाव आ गया था तो आपको यह उचित लगता था तो आर्डिनेंस के जरिये ही कुछ घोषणा कर सकते थे । आप आर्डिनेंस नहीं निकालना चाहते थे तो ऐसे एकाधिकार वाली तत्वों पर अंकुश तो लगाया जा सकता है, सरकार इसमें समर्थ है । जो न्यूनतम चीजें हैं, जो वह लागू नही करते, उनके विज्ञापन ही सरकार बन्द कर देती । आज तक आपने ऐसा नहीं किया । सीधा रास्ता यह है ।

इसके साथ जुड़ा हुआ यह भी है कि यह तो मानी हुई बात है कि एक तरफ

महंगाई बढ़ रही है और जैसे कर्मचारी काम कर रहा है, जिस सीमा में वह काम कर रहा है तो चाहे कैसा बड़े से बड़ा अवार्ड क्यों न हो, उसका न्यूनतम इंतजाम तो होना चाहिए । जैसे आवास की सुविधा है, यह मूलभूत सिद्धांत है । हम नहीं दे पाये, वह बात अलग है । आज भी हिन्दुस्तान में 9–10 करोड़ परिवारों के पास मकान रहने का नहीं है । लेकिन जिसको सुविधा मिल सकती है कानूनन मिल सकती है उस पर आप 15 से घटाकर साढ़े 6 फीसदी कम हो जाए तो क्यों नहीं उसको रोकते हैं । मुझे ऐसा लगता है कि आप उनकी राजी से नहीं कर पायेंगे ।

तीसरी चीज इससे जुड़ी हुई है कि आपको इसमें देर नहीं करना चाहिए । सभी पक्षों को आप सुन चुके हैं । सर्वोपरि हित श्रमजीवी का होना चाहिए और श्रमजीवी का हित सर्वोपरि आपके विभाग में है तो चाहे हिन्दुस्तान के बड़े अखबार वालों पर कितना बड़ा बोझ पड़ता हो, इसकी परवाह किये बिना आप कर सकते हैं । मैं चाहूंगा कि उन लोगों को कानून के हवाले आप करें जिन लोगों ने कर्मचारियों के साथ मखौल और मजाक किया है । अब तो बिलकुल साफ हो गया है कि हर आदमी से वह लोग ठेके पर काम कराते हैं, इस चीज को कम से कम आपको देखना चाहिए । ठेकेदारी प्रथा के आप भी हिमायती नहीं हैं । तो बुनियादी चीज यह है कि जब भी आप कोई फैसला करने जा रहे हैं तो श्रमजीवी पत्रकार का हित सर्वोपरि होना चाहिए । दूसरे जो लोग इस पर आनाकानी करने की कोशिश करते हैं तो साफ है कि आपके पास इतनी ताकत है कि उनके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं । कागज के घोटाले के बारे में ही हिन्दुस्तान के बड़े अखबारों के लोग जैसा करते हैं खाली इस मामले को निकालें तो सब के सब धरती पर आ जायेंगे । फिर सरकार को दबाने की उनकी हिम्मत नहीं होगी । उन लोगों को पता लगना चाहिए कि आपका इरादा मजबूत है । नहीं तो फिर 7 करोड़ का आदमी 1700 करोड़ का बन जाता है, वे जैसे कुत्ते को टुकड़े फेंकते है उसी तरह आगे भी फेंकते रहेंगे । तो मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करूंगा कि जो कर्मचारियों को तनख्वाहें मिल रही हैं, इसमें कम किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए । उनको जो मकानों की सुविधाएं थी और उसका जो प्रतिशत तय था उसमें किसी कीमत पर कम नहीं होना चाहिये । साथ ही साथ यह है कि जो अखबार आपके सुझावों को, एवार्ड के सुझावों को पूरा करने की कोशिश न करें उनको विज्ञापन देना बन्द कर दें उनका कोटा खत्म कर दें । मैं तो यहां तक चाहूंगा कि श्रमजीवी पत्रकारों को ऐसे अखबार दे दिये जायें वे ही इन अखबारों को चलायें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : उपसभापतिजी, मैं अपने इन विद्वान सदस्य की भावनाओं का आज से ही नहीं बल्कि अपने विद्यार्थी जीवन से आदर करता रहा हूं । जो भी अपने आदर्शों और विचारों को यहां व्यक्त किया, इतना अवसर नहीं है कि सीमित समय के अन्दर मैं उनके जो विचार और भावनाएं हैं उनसे सही शब्दों और सभी बातों में सामंजस्य व्यक्त कर सकूं । इतना ही कहना चाहता हूं कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिये जितनी उनकी सहानुभूति है उससे, तथा हमारा प्रयास है कि हम व्यावहारिक रूप में जो भावनाएं उनकी हैं उनसे, अपने को संजोये रखें । यही प्रयास हमारा होगा ।

जहां तक उन्होंने कहा है कि इसमें देर क्यों हुई है तो उसके कारणों का उल्लेख मेरी सहयोगी मंत्री अपने वक्तव्य में दे चुकी हैं । यह कोई जानबूझ कर नहीं हुआ है ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जो कठिनाइयां भिन्न-भिन्न आई हैं उसके कारण इसमें विलम्ब हुआ है। मै फिर आश्वस्त करता हूं अपने मित्र को कि इस अधिवेशन के भीतर इसमें निर्णय हो जाएगा।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : मंत्री महोदय योजना मंत्री भी हैं। साथ ही यह जो मामला है लेबर का है जो प्रेस में काम करते हैं उनके बारे में है, तो यह भी मसला उनके सामने है। आप बहुत आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं। बावजूद वर्किंग जर्नलिस्ट्स और प्रेस मालिक के कन्फ्रनटेशन के आप रास्ता निकाल सकते हैं। प्रेस का बहुत शानदार रोल रहा है। स्वतन्त्रता का झंडा उसने बुलन्द किया है। लेकिन मानोपाली प्रेस अभी भी है। फ्रीडम आफ द प्रेस खत्म हो गई है। वे बेचारे जो दिन-रात कलम घिसते है वे भी शोषित हुए हैं। उन्हें ठीक तरह से पता नहीं है कि कैसे उनका उद्धार होगा। जैसे बिरला, टाटा के खिलाफ हम अगर बोलेंगे तो अखबारों में नहीं छपेगा इसी प्रकार से जो कलम घिसते है, शोषित होते हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वे बगावत करें या अखबारों में छापें। ये समस्यायें वही हैं जो मानोपली उद्योग की होती हैं। इसलिये जो पालेकर एवार्ड है उसके बारे में मालिक कहता है कि ठीक नहीं है। मैने शुरू में कहा कि आप योजना मंत्री भी है और सारी अर्थ व्यवस्था को आयोजित कर रहे है। प्रेस एक उद्योग है लेकिन प्रेस आज वह प्रेस नहीं है जैसा पहले था यानी मराठा प्रेस चलता था या हरिजन को मोहनदास कर्मचन्द गांधी चलाते थे या दूसरे अखबार वाले चलाते थे। यह उसी तरह के मुनाफे का उद्योग है जैसे चीनी मिल का है या दूसरे उद्योग हैं। आप अखबारों को देखते हैं उसमें एडवर्टीजमेंट्स भरे रहते है। इससे वह मुनाफा कमा रहे हैं। मैं कहता हूं जो मजदूर इसमें काम करते हैं उन सब को टी०ए० डी०ए० वगैरह मिलना चाहिये। मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि यह जो प्रेस है पिछले पांच साल में उनका प्रोफिट कहिये, इन्कम कहिये कितना बढ़ा है। इससे हम यह अंदाजा लगा सकेंगे कि अब वे पे-स्केल देने मे समर्थ हैं या नहीं। जैसा आपके जवाब में है कि एवार्ड अपनी लाइन से आगे चला गया है, टर्मस् आफ रिफरेंस से हट गये हैं। इनके पिछले पांच सालों में कितने एसेट्स बढ़े हैं, यह स्पष्ट रूप से बताया जाय। इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मोनोपोली प्रेस को कंट्रोल करने के बारे में आप क्या सोच रहे है और क्या आप कोई कानूनी प्रतिबन्ध लगाने के बारे में सोच रहे हैं जिस प्रकार से पब्लिक सैक्टर में होता है? क्या आप प्रेस को नेशनलाईज करने की बात सोचते है? अब समय आ गया है जब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। मंत्री महोदय को प्रेस को प्लान करने के संबध में सोचना चाहिए। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पार्टी प्रेस को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनके अन्तर्गत प्रेस चलता है, क्या आप उसको नेशनेलाइज करेंगे? तीसरा और अंतिम सवाल मेरा यह है कि प्रेस में काम करने वाले कर्मचारियों के पे-स्केल में सुधार करने के साथ-साथ क्या आप इस बारे में भी सोच रहे है कि कोई इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे प्रेस के मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन हो? आज जो झमेले पैदा होते हैं और जो समस्याएं पैदा होती हैं उनको हल करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि मजदूरों का पार्टिसिपेशन उद्योगों में हो। हमारे देश में जो वर्किंग जरनैलिस्ट्स और नान-वर्किंग जरनैलिस्ट्स प्रेस में काम करते हैं उनका प्रेस के मैनेजमेंट में कितना पार्टिसिपेशन हो और उनके सहयोग से प्रेस को चलाया जाय, क्या इसको बढ़ावा देने के लिए आप तैयार हैं? ये मेरे तीन सवाल है जिनका मंत्री महोदय उत्तर देने की कृपा करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, विद्वान सदस्य ने बड़े-बड़े समाचार-पत्रों की

आमदनी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाही है। अगर वे सही जानकारी और आमदनी बता दें तो मैं उनका बहुत अनुग्रहीत होता। वस्तुतः यह भी तो विवाद का विषय है।

लेकर एवार्ड के बारे में भी श्रमजीवी पत्रकारों की ओर से एक यह विवाद का विषय उठाया गया है कि बहुत से समाचार-पत्र अपनी सही आमदनी नहीं बताते हैं। यही विवाद का प्रश्न है। लेकिन जहां तक उन्होंने वैधानिक और वैचारिक जगत के स्तर पर इस प्रश्न को उठाया है उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का प्रश्न है, श्रमिकों को प्रबन्ध में कितना सहगामी बनाया जाय, इसका सवाल है, ये प्रश्न पालेकर एवार्ड से भिन्न है। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। लेकिन यह प्रश्न अलग है। मैं चाहूंगा कि विद्वान सदस्य से इस बारे में परामर्श कर सकूं और पत्रकार जगत किस प्रकार से प्रबन्ध में सहगामी हो सके, इसके संबंध में उनके विद्वतापूर्ण सुझाव अलग से चाहूंगा।

श्री शिव चन्द्र झा : आपने पार्टी प्रेस के बारे में कुछ नहीं बताया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Special Mentions. I would request hon. Members to take very little time so that we can finish them. Shri Nanda.

REFERENCE TO THE STUDENTS' AGITATION IN ORISSA

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Mr. Deputy Chairman, Sir, the situation in Orissa is very grave. (*Interruptions*). An unprecedented agitation started in the third week of September and it has not abated. On the contrary, it is gaining momentum day by day and has by now engulfed the entire western Orissa region. It is fast spreading to coastal Orissa, Sir, today a massive demonstration was organised before the Orissa Secretariat which is situated in Bhubaneswar and all kinds of consequences have followed. I do not want to describe them in detail at this stage. Sir, the situation has cost the businessmen of western Orissa properties worth crores of rupees. Students have missed their classes for more than two months. Now an All Orissa Students Action Council has been formed and they have presented a charter of demands. Their demands are: (1) Arrest and punishment of all those responsible for assaulting students. (2) Unconditional release of all students and withdrawal of cases against them. (3) Adequate compensation for victims of the police action. (4) Strong action against hoarders and black-marketeers and profiteers. (5) Seizure of black money and unaccounted property. (6) Supply of essential commodities at fair prices, (7) making education free up to 11th class, and (8) relief and rehabilitation of flood victims.

In a nutshell, in September there was a very severe flood in Orissa. Students were collecting funds. There was a clash between the trading community and the students. Some students were very seriously injured. They were hospitalised. From then on violence started. Anti-social elements came into the picture. There was loot and arson resulting eventually in police firing and death of a number of innocent persons, particularly of a youngman, a fisherman, at Bimka, and another person whose name is Jagatram Pansari of Titlagarh. Now, thousands of students have been arrested and though the Chief Minister asserted. . . (*Time bell rings*) Sir, I have taken less than two minutes. I am trying to conclude...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, you have taken three minutes.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Anyway, I am concluding.

Though thousands of students have been arrested and though the Chief Minister asserted that he would not